



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 326]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 24, 1973/आश्विन 2, 1895

No. 326]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 24, 1973/ASVINA 2, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September 1973

S.O. 514(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 192E, dated the 31st March, 1973, the Central Government hereby directs that every employer in relation to an establishment exempted under clause (a) or clause (b) of sub-section (1) of section 17 of the said Act or in relation to an employee or a class of employees exempted under paragraph 27, or as the case may be, paragraph 27A of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, shall transfer the monthly provident fund contributions within fifteen days of the close of the month to the Board of Trustees, duly constituted in respect of that establishment, and that the said Board of Trustees shall invest every month, within a period of two weeks from the date of receipt of the said amount from the employer the provident fund accumulations, that is to say, the contributions, interest and sundry receipts as reduced by any obligatory outgoings, in accordance with the following pattern, namely:—

- (i) State Government securities and State or Central Government guaranteed securities—25 per cent.
- (ii) Post Office Time Deposits and Small Savings.—75 per cent.

The above pattern will be in force for the period from 1st October, 1973 to 31st March, 1974.

2. All re-investment of provident fund accumulations (whether invested in securities created and issued by the Central Government or in savings certificates issued by the Central Government or in securities created and issued by a State Government) shall also be made according to the pattern mentioned in paragraph 1 above.

3. The Board of Trustees shall formulate proper procedure for prompt investment or reinvestment of accumulations in accordance with the aforesaid direction and shall have it approved by the Regional Provident Fund Commissioner concerned.

[No. G. 27035(24)/73-PF.I/I.]

D. S. NIM, Jt. Secy.

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 1973

क्रा० आ० 514 (अ).—कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) धारा 17 की उपधारा (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का० अ० 192इ, दिनांक 31 मार्च, 1973 का अधिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के खण्ड (क) या (ख) के अधीन छूट प्राप्त स्थापन से सम्बद्ध या कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 27 या, यथास्थिति, पैरा 27-क के अधीन छूट प्राप्त किसी कर्मचारी, या कर्मचारियों के वर्ग से सम्बद्ध प्रत्येक नियोजक भविष्यनिधि के मासिक अभिदाय उस स्थापन की बाबत सम्यक् रूप से गठित न्यासी-बोर्ड को भासान्त के पन्द्रह दिन के भीतर अन्तरित कर देगा और उक्त न्यासी-बोर्ड भविष्य निधि संचयनों को, अर्थात् अभिदायों, ब्याज और विविध प्राप्तियों को, बाध्यकर निर्गमों को कम करके, निम्नलिखित नमूने के अनुसार हर मास, नियोजक से उक्त रकमों की प्राप्ति की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर विनिहित करेगा, अर्थात् :—

(i) राज्य सरकार प्रतिभूतियों, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों

द्वारा गारण्टी-कृत प्रतिभूतियों में 25%

(ii) डाकघरों में आवधिक जमाओं और लघु बचतों में 75%

उपर्युक्त नमूना प्रथम अक्टूबर, 1973 से 31 मार्च 1974 तक की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा ।

2. भविष्य निधि संचयनों के सभी पुनर्विनिधान (चाहे केन्द्रीय सरकार द्वारा सृष्ट और जारी की गई प्रतिभूतियों में विनिहित किए जाएं या केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए बचत प्रमाण-पत्रों में या किसी राज्य सरकार द्वारा सृष्ट और जारी की गई प्रतिभूतियों में) भी ऊपर पैरा-1 में उपर्युक्त नमूने के अनुसार किए जाएंगे ।

3. न्यासी-बोर्ड संचयनों के पूर्वोक्त निदेशों के अनुसार तत्काल विनिधान या पुनर्विनिधान के लिए उचित प्रक्रिया बनाएगा और उसे संबंधित प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त से अनुमोदित कराएगा ।

[[सं० जी०-27035(24)/73-पी०एफ० I/I]

डी० एस० नीम, संयुक्त सचिव ।